

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1286
उत्तर देने की तारीख 08/12/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्राथमिक और उच्च शिक्षा

†1286. श्री सौमैदु अ धकारी:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार का देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत अनिवार्य प्राथमिक और उच्च शिक्षा प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो शिक्षा प्रणाली के कब तक पूरी तरह लागू होने की संभावना है;

(ग) क्या एनईपी 2020 के नीति नियमों और कानून के तहत प्रत्येक विद्यालय को संबंधित राज्य से पंजीकरण और एकल इकाई के साथ बोर्ड संबद्धता प्राप्त करनी होगी; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अलग-अलग स्थानों पर एक नाम और एक ही यूडीआईएसई के साथ एक ही पंजीकरण के अंतर्गत चल रहे विद्यालयों को कब तक पंजीकरण और मान्यता के लिए नया नाम अपनाना/नाम बदलना होगा?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय के राज्यमंत्री
(श्री जयंत चौधरी)

(क) से (घ): राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में स्कूल शिक्षा की मौजूदा 10+2 संरचना को संशोधित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें 3-18 आयु वर्ग को कवर करते हुए 5+3+3+4 की नई शिक्षणक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन का प्रावधान किया गया है। तदनुसार, स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा शिक्षणक संरचना और पाठ्यक्रम रूपरेखा को 5+3+3+4 डजाइन द्वारा निर्देशित किया जाना है, जिसमें बुनियादी चरण (आंगनवाड़ी/प्रीस्कूल के 3 वर्ष + प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा 1-2 में 2 वर्ष; दोनों एक साथ 3-8 वर्ष की आयु को कवर

करते हैं), प्रारंभिक चरण (कक्षा 3-5, 8-11 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), मडल चरण (कक्षा 6-8, 11-14 वर्ष की आयु को कवर करते हैं), और माध्यमिक चरण (कक्षा 9-12 दो चरणों में, अर्थात्, पहले में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14-18 वर्ष की आयु को कवर करते हैं)।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-आधारभूत (एनसीएफ-एफएस) और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-एसई) की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, एनईपी 2020 इसके कार्यान्वयन के लिए व भन्न समय-सीमाओं के साथ-साथ सद्धान्त और कार्यप्रणाली प्रदान करती है। इसमें 2030-40 के दशक में पूरी नीति के परिचालन की भी परिकल्पना की गई है, जिसके पश्चात एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा संवधान की समवर्ती सूची में आती है और अधिकांश विद्यालय संबंधित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य विद्यालयों का पंजीकरण तथा उनका संबंधित बोर्डों से संबद्ध होना भी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा, निर्धारित मानकों और नियमों का अनुपालन करते हुए एनईपी 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी संबंधित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में ही आती है।

यूडाइस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औपचारिक तथा विशेष शिक्षा प्रदान करने वाले उन विद्यालयों द्वारा सुव्यवस्थित डेटा रिपोर्टिंग को सुगम बनाता है, और जो राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या निजी शिक्षा बोर्डों (जैसे सीबीएसई, आईसीएसई, कैम्ब्रिज आदि) से संबद्ध हैं। इसे देश में एक मानकीकृत 'डेटा कैप्चर फॉर्मेट' का उपयोग करके विश्वसनीय और तुलनात्मक सूचना को ऑनलाइन, वास्तविक समय में कुशलतापूर्वक संकलित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ब्लॉक, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा डेटाबेस का व्यापक रूप से निगरानी और प्रबंधन किया जाता है।
